



वी. चेट्टियार

कार्यकारी संपादक
8898800908

हिन्दी साप्ताहिक

RNI No.: MAHHIN/2023/89178

एकता केसरी

EKTA KESARI

Issue: 2 • Volume: 12 • Hindi Weekly • Mumbai, Friday 18 to 24 April 2025 • Price 5/- • Page 8

महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना हो जाएगी बंद?

500 रुपये किशत पर पहली बार अजित पवार ने खोला मुंह

मुंबई : महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना को लेकर फिर से माहौल गरमा गया है। इसकी वजह भी वैसी ही है। विधानसभा चुनाव के समय तत्कालीन महायुति सरकार ने लाडकी बहिन योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत लगभग 2 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही थी। चुनाव के दौरान महायुति के नेताओं ने वादा किया था कि अगर उनकी

सरकार फिर से आती है, तो वे लाडकी बहनों को 2100 रुपये की मदद देंगे। इसके बाद राज्य में महायुति की ही सरकार आई। लेकिन अब लाडकी बहिन योजना के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसके लिए आवेदनों की जांच शुरू कर दी गई है। इस जांच में लाखों महिलाएं पहले ही अपात्र हो चुकी हैं। अब एक और बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना का लाभ लेने वाली 8 लाख महिलाओं को



1500 रुपये की जगह सिर्फ 500 रुपये का लाभ मिलेगा। इस बात को लेकर विपक्ष राज्य सरकार पर निशाना साध रहा है। अब इस प वित्त मंत्री अजित पवार और महिला-बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे की प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय राऊत ने साधा निशाना ठाकरे गुट के सांसद संजय राऊत ने कहा कि लाडकी बहनों को ही सरकार से सवाल पूछने चाहिए। जिन लाडकी बहनों से 1500 शेष पृष्ठ २ पर

पुलिस के साथ झूमाझटकी, घायल हुई सांसद वर्षा गायकवाड़, कांग्रेस बोली- तानाशाह सरकार

मुंबई: विपक्ष खासकर कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई एक बार फिर शुरू हो गई है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के खिलाफ हाल ही में की गई 'ईडी' की कार्रवाई के विरोध में मुंबई में कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। सांसद एवं मुंबई प्रदेश अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में 'ईडी' कार्यालय पर मोर्चा भी निकाला गया। लेकिन 'ईडी' कार्यालय की ओर बढ़ रहे मोर्चे को पुलिस की ओर से रोकने के प्रयास के दौरान सांसद वर्षा को हल्की चोट लग



गई। कांग्रेस ने इसे बीजेपी सरकार की तानाशाही करार दिया है। सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि मुंबई भाजपा के तानाशाही शासन के खिलाफ कांग्रेस की ओर से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक

तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। 'ईडी' कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान फडणवीस सरकार ने पुलिस का इस्तेमाल करके विरोधियों का दमन करने का प्रयास किया है। मोदी की तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस का संघर्ष जारी रखने का प्रण दोहराते हुए वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि मुझे और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अमानवीय तरीके से पीटा गया और हिरासत में लिया गया। मुंबई पुलिस की कार्रवाई को दमनकारी करार देते हुए सांसद वर्षा ने राज्य सरकार की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा शेष पृष्ठ २ पर

पायलट था, को-पायलट बना दिया शिंदे का फिर छलका दर्द



अमरावती: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी, शिवसेना (शिंदे गुट) व राका (अजित पवार) के गठबंधन वाली महायुति सरकार के गठन को लगभग 4 महीने बीत चुके हैं लेकिन दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने का मलाल उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने मन से निकाल नहीं पा रहे हैं। अमरावती एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर कुर्सी बदलने का उनका दर्द एक बार फिर छलक उठा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि शेष पृष्ठ २ पर

बाबरी गिरने पर अटल-आडवाणी ने मांगी थी माफी, बालासाहेब ने नहीं नासिक में गरजे उद्धव ठाकरे

नासिक: उद्धव ठाकरे ने नासिक में अमित शाह के बयान पर जवाब दिया कि शिवाजी महाराज की विरासत महाराष्ट्र से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने मांग की कि अगर शाह वाकई शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं तो उन्हें शिवाजी जयंती पर पूरे देश में छुट्टी घोषित करना होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवाजी महाराज की विरासत विश्व स्तर पर

फैली है। उन्होंने शिवाजी जयंती पर पूरे देश में छुट्टी की मांग करते हुए कहा कि यह राजा के प्रति सच्चे सम्मान का प्रतीक है। उद्धव ठाकरे ने आलोचना करते हुए कहा आज हिंदुत्व के बारे में हमें सिखाने वाले लोग उभरे हैं। उनके पूरे सफर को देखें तो वे बहुत गहराई तक जाएंगे। मोदी कहते हैं कि कांग्रेस को एक मुस्लिम अध्यक्ष नियुक्त करना



चाहिए और एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। लेकिन मुझे एक-दो बातें अच्छी लगीं। कांग्रेस के क्षेत्रीय अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि आरएसएस को संघ परिवार का प्रमुख दलित नेता नियुक्त करना चाहिए और एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। आइए इसे एक चुनौती बनाएं। अगले साल, आरएसएस 100 साल का हो जाएगा, और कांग्रेस

125 साल की हो जाएगी। आरएसएस प्रमुखों और कांग्रेस अध्यक्षों की एक सूची बनाएं, पहचानें कि कौन दलित था और कौन मुस्लिम था, और इसे लोगों के सामने पेश करें। लेकिन जब आप खुद सूखे हों तो लोगों को उपदेश देना व्यर्थ है। हिंदुत्व की विचारधारा नहीं त्यागी शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने हिंदुत्व शेष पृष्ठ २ पर



संपादकीय

वोट बैंक की राजनीति खत्म करते मोदी

वक्फ कानून में संशोधन एक ऐसा पैमाना था, जिस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दोनों राजनीतिक मददगारों चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को परखा जाना था। चूंकि आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनावों के साथ ही विधानसभा चुनाव हो गए थे, इसलिए नायडू के लिए तुरंत कोई बड़ा संकट नहीं था, लेकिन बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है।

इसके बावजूद जिस तरह से जदयू वक्फ संशोधन कानून बनाने के लिए मोदी के साथ मजबूती से खड़ी हुई, उसे इतिहास में याद किया जाएगा। बिहार चुनावों के बाद ही जदयू के इस जोखिम का सही परिणाम पता चल सकेगा, लेकिन इससे इतना तो तय हो गया है कि देश में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति का दबाव समाप्त सा हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के लोग लगातार धमकियां देते रहे, लेकिन मुसलमानों का डर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को उनका मतपरिवर्तित करने के लिए तैयार नहीं कर पाया। जिस दौरान देश में गाजा से लेकर वक्फ के मुद्दे पर कथित सेक्युलर राजनीति करने वाले नेता मुसलमानों का डर बढ़ा रहे थे, उसी दौरान मोदी को इस्लामिक देश कुवैत अपने सबसे बड़े सम्मान से नवाज रहा था।

मोदी की शुरुआती राजनीति ही वोट बैंक की राजनीति के दबाव से बाहर निकलने की रही है। गुजरात में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो सबसे बड़ा संकट राज्य के सबसे शक्तिशाली पटेल वोट बैंक के दबाव से बाहर निकलने का था। मोदी ने बड़े सलीके से हिंदूहृदय सम्राट वाली छवि में पटेल नेताओं को इतना सीमित कर दिया कि उनके गुजरात से निकले एक दशक होने के बाद भी गुजरात का मतलब मोदी ही है। उन्होंने अन्य जातीय समूहों का दबाव समाप्त कर दिया है और हिंदू पहचान के साथ सभी जातीय समूहों का बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ जुड़ चुका है। मोदी अब यही कोशिश मुस्लिम वोट बैंक के मामले में भी कर रहे हैं। वह मुस्लिमों को भारतीय पहचान सबसे पहले रखने के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी हिंदू एकता से आगे 'हम भारत के लोग' की अवधारणा को मजबूत करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।

मोदी देश के दूसरे नागरिकों की ही तरह मुसलमानों के मन से भी यह आकांक्षा समाप्त कर देना चाहते हैं कि हमारी जाति, हमारे क्षेत्र, हमारे मजहब के लिए सरकार क्या कर रही है। मोदी यह स्थापित कर देना चाहते हैं कि देश की बेहतरी तभी हो सकती है, जब सबके लिए बेहतरी के एकसमान अवसर सरकारी नीतियों से मिलें। यही वजह है कि मोदी सरकार की योजनाओं में किसी भी वर्ग के लिए भेदभाव का छंटॉक भर का भी आरोप नहीं है। भाजपा शासित राज्यों में दंगे न्यूनतम होते हैं, यह बात भी आंकड़ों से स्थापित हो चुकी है। विपक्षी पार्टियां एक समय में पिछड़ों और अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को भी भाजपा के विरुद्ध खड़ा करती थीं, लेकिन उनसे संवाद के लिए भाजपा के पास हिंदू पहचान वाला बड़ा आधार था। मुस्लिमों को भाजपा का स्वाभाविक दुश्मन बताने में विपक्षी पार्टियों को इसलिए आसानी होती है, क्योंकि राष्ट्रवाद से लेकर देश और देश की संस्कृति के मुद्दों पर भाजपा की मुखरता मुसलमानों को अपनी पहचान को लेकर सतर्क करने लगती है विपक्षी पार्टियां जानबूझकर मुगल आक्रांताओं से जुड़ी मुस्लिम पहचान को उभारकर उनके भीतर एक डर बैठाना चाहती हैं, लेकिन मोदी ने मुसलमानों के बीच पैठ बनाने का रास्ता सीख लिया है। दरअसल मोदी ने शिया, सुन्नी, दाऊदी बोहरा, खोजा, गुजराती शेख, मेनन, पठान आदि के विभाजन को ही उनके बीच पहुंचने का आधार बनाया है।

कर्तव्य पालन में अनदेखी का नतीजा, कोर्ट को सुनवाई की समयसीमा निर्धारित करने का अधिकार

सर्वोच्च न्यायपीठ ने दलबदल की याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कहा है कि इनसे जुड़े निर्णय में देरी से संविधान की दसवीं अनुसूची के उद्देश्य विफल हो सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि कोर्ट को सुनवाई की समयसीमा निर्धारित करने का अधिकार है, लेकिन न्यायालय याचिकाओं के परिणाम नहीं निर्धारित कर सकता। यह निर्धारण सदन के सभापति करते हैं। कोर्ट ने मणिपुर विधानसभा मामले (2020) सहित कई मामलों में निर्णय की समयसीमा निर्धारित करने की अपेक्षा की है। एक मामले (1992) में कहा कि कार्यवाही में देरी की स्थिति में न्यायालय को हस्तक्षेप का अधिकार है। 1994 में रवि एस. नायक बनाम भारत संघ मामले में अध्यक्ष की निष्पक्षता पर भी टिप्पणी की गई थी। इसी तरह कोर्ट ने तमिलनाडु के मामले में 10 विधेयकों को लंबे समय तक विचारार्थ रखने को लेकर राज्यपाल पर तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के निर्णय की कोई समयसीमा नहीं है, पर कोर्ट ने विधेयकों को सीधे मंजूर करने का फैसला अनु. 142 की विशेष शक्तियों के अंतर्गत कर दिया।

कोर्ट ने राष्ट्रपति की एवं अपनी शक्तियों का अलग-अलग उल्लेख किया है। दोनों आदरणीय हैं, मगर अधिकारों की तुलना विचारणीय है। प्रथमदृष्टया संविधान के दोनों प्रविधानों में टकराव दिखाई पड़ रहा है। यह उचित नहीं है। यदि संवैधानिक संस्थाएं ठीक से कर्तव्यपालन करें तो संवैधानिक राजव्यवस्था भी ठीक चलती है। कर्तव्यपालन न करें तो कठिनाइयां आती हैं। संसद और विधानमंडलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 102 एवं 191 में सदस्यों के लिए अनेक अयोग्यताएं निर्धारित हैं। संसद ने दलबदल विरोधी अधिनियम बनाया था। पिछली सदी के सातवें दशक में थोक के भाव दलबदल हो रहे थे। हरियाणा के एक नेता ने 1967 में एक दिन में तीन बार दलबदल किया था। तभी 'आया राम गया राम' का मुहावरा चला। इसके बाद कई राज्यों में दल टूटकर सरकारें बनीं। जनतंत्र में दल विचार के आधार पर बनते हैं। विचार निष्ठा लोकप्रिय बनाती है। राजनीतिक दल व्यक्ति को चुनाव लड़ाते हैं। वह जिस दल से निर्वाचित होता है उसे छोड़ देना मतदाता के साथ धोखाधड़ी एवं वैधानिक अनैतिकता है। 1985 में

राजीव गांधी के नेतृत्व में 404 कांग्रेसी सांसद थे। कहा जाता है कि उन्होंने दलबदल के भयवश 52वां संविधान संशोधन पारित करवाया था। यही संविधान की दसवीं अनुसूची है। इसमें दलीय सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों के एक साथ दलबदल करना दलों का विलय माना गया था। अजीब है कि जो काम एक व्यक्ति करे तो पाप है। एक तिहाई करें तो पुण्य। अनेक राज्यों में दलबदलुओं को लाभ हुआ। वे रातोंरात मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों से लाभान्वित हुए। 91वें संविधान संशोधन द्वारा विलय की सुविधा में सख्ती आई। एक तिहाई की जगह दो तिहाई सदस्यों का प्रविधान किया गया। दो तिहाई सदस्यों का एक साथ दलबदल आसान नहीं था। कुछ राज्यों में धीरे-धीरे एक दो सदस्य किस्तों में आते गए और दलबदल को विलय माना जाता रहा। दलीय अनुशासन भी दलबदल का मुख्य तत्व बना। सदस्य द्वारा विधानमंडल दल के प्राधिकारी के जारी निर्देशों को न मानना अथवा प्राधिकारी के निर्देशानुसार मतदान न करना या मतदान से दूर रहना भी दलबदल कानून के अधीन दंडनीय है। व्यक्ति या समूह द्वारा जानबूझकर दल त्याग

भी संभव है। कई बार दल अपनी विचारधारा बदलते हैं। कुछ सदस्यों को यह असहनीय लगता है। वे सदन में अपने दल के विरुद्ध बोलते हैं। विचार अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार भी दलीय अनुशासन में नहीं मिलता। जबकि अनु. 105 एवं अनु. 194 में सदस्यों को विचार अभिव्यक्ति की असीम स्वतंत्रता है। कई बार सदस्य को अपने अथवा दल के विचार बदल जाने के कारण भी कठिनाई आती है। तब दलीय अनुशासन तानाशाही हो जाता है। राजनीतिक स्थिरता के लिए दलबदल पर रोक भी जरूरी है, लेकिन इसे सालाना बजट या अविश्वास प्रस्ताव जैसे महत्वपूर्ण अवसरों तक सीमित रखना होगा। असहमत होने का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार का हिस्सा है। इस कानून ने राष्ट्रीय विमर्श आधारित लोकतंत्र की जगह दलों और सदस्य संख्याओं का लोकतंत्र बना दिया है।

यह भी याद रहे कि असहमति और दलबदल एक नहीं है। असहमति मौलिक अधिकार है और दलबदल अनैतिक। संविधान ने दलबदल के मामलों की सुनवाई का अधिकार सदन के अध्यक्षों/सभापतियों को दिया है।

पृष्ठ 1 का शेष

महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना हो जाएगी बंद?

रुपये के बदले वोट खरीदे गए, उन वोटों की कीमत अब 500 रुपये पर आ गई है। वह कल शून्य रुपये पर आ जाएगी। इस राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर है। कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। लेकिन अब इस राज्य को चलाना आर्थिक रूप से आसान नहीं रह गया है। इसका कारण यह है कि पिछले साढ़े तीन सालों में इस राज्य की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। इसके बाद सरकार की ओर से स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। अजित पवार ने क्या कहा? उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि हमारा कहना है कि किसी भी एक योजना का लाभ लें। महिलाओं को केंद्र की योजना मिलेगी ही। केंद्र की योजना का और राज्य सरकार का कोई संबंध नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को यह योजना दी है। अगर यह लाभ नहीं मिल रहा है तो डेढ़ हजार रुपये का लाभ लें। कौन सा लाभ लेना है, यह तय करने का अधिकार हमने अपनी लाडकी बहनों पर छोड़ दिया है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की सरकार की 'लाडकी बहिन' योजना जारी रहेगी और इसे खत्म करने का कोई सवाल ही नहीं है। योजना के कार्यान्वयन के लिए बजटीय आवंटन किया जा चुका है और इसे खत्म करने का कोई सवाल ही नहीं है। अर्थ राज्यमंत्री का भी स्पष्टीकरण राज्य के अर्थ राज्यमंत्री आशीष जायसवाल ने भी इस बारे में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस योजना के GR में कोई भी शर्त नहीं बदली है। इसलिए अगर किसी ने उन शर्तों के खिलाफ जाकर लाभ लिया है, या अमीर घर की महिलाओं ने लाभ लिया है

बाबरी गिरने पर अटल-आडवाणी

की विचारधारा का त्याग नहीं किया है, लेकिन उनकी पूर्व सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का हिंदुत्व का 'सड़ा हुआ' संस्करण उन्हें स्वीकार्य नहीं है। ठाकरे ने उत्तर महाराष्ट्र के नासिक में शिवसेना यूबीटी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह भी सुझाव दिया कि राज्य की भाजपा-नीत सरकार को मुंबई में राजभवन परिसर को छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक में बदल देना चाहिए तथा राज्यपाल आवास किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर देना चाहिए। भाजपा से 2019 में अलग हो चुके ठाकरे ने कहा कि अविभाजित शिवसेना के बिना केंद्र और राज्य की मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी उस स्थिति में नहीं पहुंच पाती कि अयोध्या में राम मंदिर बन सके।

पायलट था, को-पायलट बना दिया

हमसे पहले वाली महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान विकास की तमाम परियोजनाएं बंद कर दी गई थीं। लेकिन हम सत्ता में आए और राज्य का विकास एवं कल्याणकारी योजनाएं फिर शुरू हुईं। मैं उस विमान का पायलट था। उस समय देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मेरे को-पायलट थे। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस हमारे पायलट बन गए हैं और अजित पवार के साथ मुझे विमान को को-पायलट बना दिया गया है। बुलेट ट्रेन की गति से आगे बढ़ना है – एकनाथ शिंदे एकनाथ शिंदे ने कहा कि पिछली सरकार (उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी) के कार्यकाल में विकास की सभी परियोजनाएं ठप हो गई थीं। उन्होंने हर जगह स्पीड ब्रेकर लगा दिए थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद हमने सभी स्पीड ब्रेकर हटा दिए। महायुति सरकार के शासनकाल में राज्य की प्रगति हुई है। भले ही हमारी कुर्सी बदल गई हो, लेकिन विकास के धरातल पर यह प्रगति अभी भी जारी है। राज्य में अब कई परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। महायुति सरकार का इंजन अब तो यह और तेज चलने लगा है। हमें बुलेट ट्रेन की गति से आगे बढ़ना होगा। इस हवाई अड्डे की वजह से अमरावती का विकास हो रहा है। हवाई अड्डे से नागरिकों और किसानों को बहुत लाभ होगा। देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती एयरपोर्ट का किया उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार 16 अप्रैल को अमरावती एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए इसे जिले के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए पहले विमान से वे स्वयं अमरावती पहुंचे हैं।

पुलिस के साथ झूमाझटकी,

कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र को बचाने और लोगों के अधिकारों के लिए लगातार लड़ती रही है। क्या है मामला? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेसी सांसद सोनिया गांधी एवं उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर से केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रडार पर आ गए हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है तो वहीं एक अन्य मामले में रॉबर्ट वाड्रा को मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए कांग्रेस आरोप पत्र को फर्जी बता रही है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरने लगे हैं।

मुंबई पर 26 नवंबर को ही क्यों हुआ था हमला ? तहव्वुर राणा को थी हर एक जानकारी, जानें सबकुछ

मुंबई: मुंबई पर 26 नवंबर 2008 को ही आतंकी हमला क्यों किया गया, इसका जवाब छिपा है एक सुनियोजित रणनीति में। आतंक के आकाओं ने हमले के लिए वो तारीख चुनी जब भारत की समुद्री सुरक्षा प्रणाली अस्थायी रूप से कमजोर पड़ गई थी। और इसके मास्टरमाइंड NIA की कस्टडी में रह रहे आतंक के खामोश डॉक्टर यानी तहव्वुर राणा है जिसे 26/11 हमले की हर जानकारी थी। 26/11 जांच से जुड़े मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की रिपोर्ट के अनुसार आतंकी डेविड हेडली ने अप्रैल 2008 में अमेरिका यात्रा के दौरान शिकागो में तहव्वुर राणा से मुलाकात की थी। मई में हुई इस मुलाकात में हेडली ने राणा को बताया था कि मुंबई हमले को फिलहाल टाल दिया गया है क्योंकि समुद्री लहरें अनुकूल नहीं थीं। पहले से टारगेट पर था ताज होटल

हेडली ने राणा को बताया था कि मार्च 2008 में एक 'अमीर' (हाफिज सईद के लिए प्रयुक्त शब्द) ने बताया था कि ताज होटल हमला का मुख्य टारगेट होगा। जुलाई-अगस्त में समुद्र में ज्वार-भाटा होने के कारण हमला स्थगित किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, राणा को हमले की पूरी जानकारी थी। जैसी जानकारी लखवी, हाफिज सईद और अन्य साजिशकर्ताओं को थी। बावजूद इसके, FBI से पूछताछ के दौरान उसने झूठ बोला कि उसे हमले की कोई जानकारी नहीं थी। अब NIA अधिकारी राणा से जुड़े सभी सवालों के जवाब खोजने में लगे हुए हैं। नौसेना का युद्धाभ्यास बना 'मौका' 17 नवंबर 2008 को अरब सागर के उत्तरी हिस्से में भारतीय नौसेना के युद्धपोत, गश्ती विमान और हेलिकॉप्टर 'तलवार शाखा' के तहत एक बड़े रक्षा अभ्यास में व्यस्त थे। इसका उद्देश्य पश्चिम



एशिया में भारत के ऊर्जा गलियारे की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। ये अभ्यास 22 नवंबर को DGX (डिप्लोमेसी एंड गेमिंग एक्सरसाइज) के साथ समाप्त हुआ। इसके बाद समुद्री गतिविधियाँ सामान्य हो गईं और निगरानी कमजोर पड़ गई। 'अल-हुसैनी' से भारत में प्रवेश की

साजिश इस मौके का फायदा उठाकर आतंकी जहाज 'अल-हुसैनी' भारतीय समुद्री सीमा की ओर बढ़ा। लेकिन भारतीय तट रक्षक बल की निगाहों से बचना आसान नहीं था। इसलिए 23 नवंबर को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नौका एमएफबी कुबेर

को सहायता के बहाने रोका और कब्जा कर लिया। चार मछुआरों की हत्या कर दी गई और कप्तान अमर सिंह सोलंकी को मुंबई की ओर नाव ले जाने को मजबूर किया गया। मुंबई पहुंचने से पहले GPS से जांच मुंबई के तट से लगभग 4 समुद्री मील पहले कुबेर को रोककर, आतंकी अबू इस्माइल ने जीपीएस

की मदद से दूरी मापी। करीब 3 घंटे की दूरी थी और अंधेरा हो रहा था। इस बीच एक मछुआरे की नौका ने इन्हें भ्रमित किया और समुद्र में रुकना पड़ा। कुबेर में कसाब ने कप्तान सोलंकी की हत्या कर दी और आतंकी जल्दबाजी में कुबेर को वहीं छोड़कर ट्रॉलर से बघवार पार्क पहुंचे। बघवार पार्क पर उतरने के बाद 8 आतंकी सड़क के रास्ते CSMT स्टेशन, ताज होटल और अन्य टारगेट की ओर बढ़े जबकि 2 आतंकी नाव से नरीमन पॉइंट की ओर रवाना हुए। मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में राणा को बैरक नंबर 12 में रखे जाने की संभावना है। इसको लेकर मुंबई पुलिस और जेल प्रशासन के आला अधिकारियों के बीच बैठकें जारी हैं। वर्चुअल पेशी की भी तैयारी शुरू है। सूत्रों ने बताया कि कसाब की तरह फांसी दिए जाने की चिंता राणा को भी सताने लगा है, जिसकी चर्चा उसने अपने वकीलों के साथ किया था।

चेंबूर फायरिंग केस: मुख्य आरोपी और शूटर को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि नवी मुंबई के एक बिल्डर पर हमले के एक मामले, चेंबूर गोलीबारी मामले में कथित रूप से शामिल मुख्य आरोपी और एक शूटर को शुक्रवार को मुंबई अपराध शाखा और मुंबई पुलिस के जोन 6 के पुलिस अधिकारियों ने अलग-अलग अभियानों में गिरफ्तार कर लिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, आरोपी की पहचान फिरोज बदारुद्दीन खान (54) के रूप में हुई है, जो उपनगरीय मुंबई के सांताक्रूज इलाके का निवासी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, खान को मीरा रोड (पूर्व) के नया नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र से पकड़ा गया। मुंबई अपराध शाखा की एक टीम ने उसे ट्रैक करने और पकड़ने के लिए ऑपरेशन का नेतृत्व किया। एक



अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा, चेंबूर फायरिंग मामले में मुख्य शूटर, जिसका नाम अफसर खान (20) है, को भी पकड़ लिया गया है। उसे मुंबई पुलिस के जोन 6 की टीमों ने धारावी इलाके से पकड़ा। आगे की जांच जारी है। पुलिस ने पहले कहा था कि नवी मुंबई के रहने वाले बिल्डर सदरुद्दीन खान (50) पर 9 अप्रैल को रात करीब 9.50 बजे सायन-पनवेल हाईवे पर पनवेल की

ओर जाते समय मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने हमला किया था। खान को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वह खतरे से बाहर है। दो गोलीयाँ उसके गाल पर लगीं जबकि एक गोली उसकी कार में लगी। एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, और आरोपियों को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस और उसकी अपराध शाखा की कई टीमों बनाई गई हैं। एक पुलिस अधिकारी ने पहले कहा था चेंबूर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 और 3(5) के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 3 और 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि आगे की जांच चल रही है।

महाराष्ट्र के गैंगस्टर जिया अंसारी की करतूत, IPC की धाराओं वाले केक काटकर बोला- नेक्स्ट केस का वेट, अरेस्ट

मुंबई: भांडुप का कुख्यात गैंगस्टर जिया अंसारी फिर से खबरों में है। उसकी चर्चा इस बार उसके किसी बड़े क्राइम के लिए नहीं बल्कि खुद के अनाखे जन्मदिन मनाने को लेकर है। उसने जिस तरह से अपना जन्मदिन मनाया, उसने उसे जेल सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जबकि कई संगीन अपराध करने के बावजूद वह खुला घूम रहा था। दरअसल जिया अंसारी ने अपने जन्मदिन पर खुद के ऊपर दर्ज एफआईआर वाले केक काटे। महाराष्ट्र का गैंगस्टर जिया अंसारी बीते दिनों जमानत पर बाहर था। उसने अपना जन्मदिन मनाया। जन्मदिन मनाने का तरीका ऐसा था जिससे अपराध को बढ़ावा मिले। जन्मदिन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इसके बाद पुलिस ने उसे



गिरफ्तार किया। इस तरह के थेकेक जिया अंसारी पर पहले भी कई गंभीर आरोप हैं। उस पर हत्या (IPC 302), हत्या की कोशिश (IPC 307), जबरन वसूली (IPC 387) और मारपीट (IPC 326) जैसे मामले दर्ज हैं। उसने अपने जन्मदिन पर जो केक काटे, उन पर वही IPC की धाराएं लिखीं थीं, जो उसके ऊपर दर्ज हैं। इन केक के

साथ लास्ट में एक प्रश्न चिह्न (?) वाला केक भी था। जिसे देखकर लग रहा था कि वह अपने अगले अपराध के बारे में संकेत दे रहा है। लोगों ने जताई नाराजगी कुछ लोगों का कहना है कि जिया अंसारी ने यह भी कहा, 'नेक्स्ट केस का वेट है।' मतलब, वह अगले मामले का इंतजार कर रहा है। इस घटना से भांडुप के लोग बहुत गुस्से में हैं।

स्कूल बैग की जांच में मिले चाकू और तंबाकू के पैकेट

नासिक : महाराष्ट्र के नासिक में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। इगतपुरी तालुका के घोटी गांव में एक प्राइवेट स्कूल है। स्कूल में अचानक बच्चों के बैग की जांच की गई। जांच में कुछ ऐसी चीजें मिलीं, जिसने स्कूल प्रिंसिपल लेकर

मैनजमेंट और टीचर्स को हैरान कर दिया। स्कूल के बैग में चाकू, मुक्का मारने वाले हथियार तंबाकू के पैकेट, खाली कंडोम के पैकेट और डिब्बे मिले। इसके साथ ही स्टील या एल्यूमीनियम से बने गहने भी मिले। स्कूल प्रशासन ने ये सब चीजें जब्त

कर लीं। स्कूल ने बच्चों के माता-पिता को इस बारे में बताया। बच्चों को समय-समय पर समझाया भी गया। गांव की स्कूल समिति के प्रमुख मनोज जाधव ने कहा, 'हम यह देखने के लिए जांच करते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर बच्चों के

पास ऐसी चीजें मिलती हैं जो उनके पास नहीं होनी चाहिए, तो हम माता-पिता को बताते हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बच्चे स्कूल में गलत व्यवहार न करें। इसलिए हमने ये चीजें जब्त कीं।' स्कूल कमिटी करती है स्कूल बैग की

जांच स्कूल समिति में गांव के लोग और स्कूल के अधिकारी शामिल हैं। यह समिति कक्षा VIII से X तक के बच्चों के बैग की जांच करती है। समिति माता-पिता को भी जानकारी देती है। जाधव ने बताया कि समिति दानदाताओं की मदद से छात्रों को

किताबें, यूनिफॉर्म और दूसरी चीजें भी देती है। 2022 से शुरू हुआ सिलसिला एक अभिभावक, शंकर गावित ने बताया कि 2022 में मेरे पड़ोसी के बच्चे के बैग में 300 रुपये मिले थे। स्कूल समिति ने बच्चे के पिता को बुलाया।

महाराष्ट्र में कानून या सिर्फ धनबल और बाहुबल का बोलबाला?

जानें बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस से ऐसा क्यों कहा

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शहर के एक स्कूल द्वारा अपने परिसर में होर्डिंग लगाने का विरोध करने पर उसे धमकाने के मामले में तलख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि क्या हम ऐसे राज्य में रहते हैं, जहां कानून के शासन की जगह सिर्फ धनबल और बाहुबल का बोलबाला है। कोर्ट ने संबंधित क्षेत्र के ऑडिशनल कमिशनर ऑफ पुलिस से इस संबंध में हलफनामे में स्पष्टीकरण मांगा है। यह स्कूल बांद्रा (वेस्ट) में स्थित है और IB (इंटरनैशनल बैकलॉरिएट) से संबद्ध है। यहां तीन से नौ वर्ष की उम्र के 300 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल की ओर से बॉम्बे एजुकेशन ट्रस्ट ने याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि एक मंडल ने बीएमसी की अनुमति के बिना स्कूल की दीवार पर होर्डिंग लगा दी और इस पर लाइसेंस नंबर का भी उल्लेख नहीं था।



बच्चों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता

याचिका के अनुसार, यह होर्डिंग स्कूल के बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकती है। दरअसल स्कूल के जिस हिस्से में होर्डिंग लगाई गई, वहीं पर बच्चे बस में चढ़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। ट्रस्ट ने अदालत से स्कूल की बाउंड्री वॉल

और आसपास के फुटपाथ पर लगे सभी अवैध होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर हटाने का निर्देश देने की मांग की है।

'धमकाने की प्रवृत्ति ठीक नहीं'
याचिका में यह भी कहा गया है कि मंडल की ओर से राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग करते हुए स्कूल प्रशासन को धमकाया गया। सुनवाई के दौरान

बेंच को बताया गया कि दीवार पर लगाए गए बैनर को मुंबई पुलिस और बीएमसी अधिकारियों ने हटा दिया है, लेकिन स्कूल को अप्रत्यक्ष रूप से एक संदेश भेजा गया है कि सभी उत्सवों और दूसरे मौकों पर स्कूल की कंपाउंड वॉल और परिसर में होर्डिंग लगाई जाएगी। इस पर बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दी गई जानकारी पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता है।

'धमकाने वालों पर कार्रवाई के संबंध में मांगा जवाब'

बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच ने अडिशनल कमिशनर ऑफ पुलिस से पूछा है कि वे जहां कानून का राज कायम है, यदि वहां (जैसे याचिकाकर्ता के स्कूल परिसर में) कोई जबरन बल प्रयोग कर कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई प्रस्तुत की जाएगी? 28 अप्रैल को याचिका पर अगली सुनवाई होगी।

मुंबई में इस बार सामान्य से अधिक बारिश होने के 65% चांस, महाराष्ट्र में मॉनसून को लेकर आई गुड न्यूज



मुंबई: इस बार मॉनसून में मुंबई, उपनगर और आसपास अच्छी बारिश के संकेत हैं। क्षेत्रीय मौसम विभाग के अनुसार मुंबई में सामान्य से अधिक बारिश होने की 65% संभावना का है। प्राथमिक पूर्वानुमान सही साबित हुआ, तो मॉनसून में यहां अच्छी बारिश होगी, जो मुंबईकरों के लिए राहत भरी खबर है। मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में पानी की काफी खपत है, जो यहां की झीलों से पूरी होती है। झीलों में जमा बारिश का पानी मुंबई की साल भर प्यास बुझाता है। ऐसे में, अच्छी बारिश होती है, तो मुंबईकरों को पानी कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर जगह महाराष्ट्र में पहुंचेगा मॉनसून मौसम विभाग के प्राथमिक पूर्वानुमान के अनुसार इस बार मुंबई सहित महाराष्ट्र के लिए अच्छी खबर यह है कि लगभग सभी जगह मॉनसून की उपस्थिति होगी। कई जगह नॉर्मल, तो कई जगहों पर सामान्य से अधिक तो कई क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मुंबई में होगी खूब झमाझम क्षेत्रीय मौसम विभाग की वैज्ञानिक सुषमा नायर ने बताया कि प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना 65% है। हालांकि, मौसम विभाग की एक और रिपोर्ट जारी की जाएगी, जिसमें मॉनसून के पैटर्न को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी। समुद्र से मुंबई की ओर आनेवाली हवाएं सक्रिय हो गई हैं, नतीजतन महानगर में दिन के तापमान गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को मुंबई का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन बुधवार को यह कम हो कर 34.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है।

क्या बीजेपी को छोड़कर किसी और से गठबंधन करेंगे एकनाथ शिंदे? महाराष्ट्र में क्यों छिड़ी है ऐसी चर्चा

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहने के बाद अब उप मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल रहे एकनाथ संभाजी शिंदे क्या फिर से चौंकाएंगे? मंगलवार को एकनाथ शिंदे ने आश्चर्यजनक तौर पर मुंबई में मनसे चीफ राज ठाकरे के घर पर स्नेह भोज किया। इसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति गरमा गई है। चर्चा हो रही है कि क्या एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना बीएमसी और दूसरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मनसे के साथ गठबंधन करने वाले हैं। कहते हैं राजनीति में जो दिखता है वह होता नहीं है। राजनीतिक चर्चाओं के बीच शिंदे ने मीडिया से कहा कि वे राज ठाकरे से मिलने गए थे। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच बाला साहब ठाकरे की यादों को लेकर बात हुई। बेटे की हार के बाद पहली मुलाकात शिंदे जो भी कहें लेकिन महायुति में काफी समय से अहससज महसूस कर रही शिवसेना और मनसे की दोस्ती की संभावनाओं



को खारिज नहीं किया जा सकता है। विधानसभा चुनावों में यह एकनाथ शिंदे ही जिन्होंने बीजेपी के कहने के बाद भी माहिम से अपना प्रत्याशी वापस नहीं लिया था। इसके चलते राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की हार हुई थी। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। यह सब तब हुआ था जब राज ठाकरे और उनकी पत्नी ने बेटे को जिताने के लिए पूरी ताकत

झोंक दी थी। तब यह माना गया था कि शिंदे के कैडिडेड खड़ा रखने से अमित ठाकरे की हार हुई। विधानसभा चुनावों के कई महीनों बाद दोनों नेताओं के एक साथ आने के बाद चर्चा हो रही है कि क्या शिंदे मुंबई-ठाणे समेत मराठी बेल्ट यानी कोकण तब कोई नया समीकरण बनाते जा रहे हैं। मुलाकात से गरमाई राजनीति एकनाथ शिंदे की राज ठाकरे से

मुलाकात पहली बार नहीं हुई है, वह बतौर सीएम भी कई बार राज ठाकरे से मिले हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में दोनों के बीच दरार जगजाहिर हो गई थी। कुछ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि दोनों मिले होंगे तो राजनीतिक चर्चा नहीं होगी, लेकिन यह मुलाकात दरार पाटने की कोशिश अधिक है। शिंदे की ठाकरे से मुलाकात के बाद कहा गया कि

दोनों की विचारधारा एक जैसी है। इसके बाद ही ये अटकलें लगीं कि खुद को मजबूत करने के लिए क्या शिंदे कोई नई युति यानी गठबंधन की सोच रहे हैं। लोकसभा चुनावों में राज ठाकरे एनडीए का हिस्सा बने थे लेकिन तब कोई फायदा हीं दिखा था।

विचारधारा एक 'दुश्मन' भी सेम राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शिवसेना ने ही विधानसभा चुनावों में मनसे को गठबंधन का विरोध किया था। अब विधानसभा चुनावों के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली बैठक हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राज ठाकरे ने विधानसभा चुनावों में अजित पवार की पार्टी के 47 सीटें जीतने पर खास व्यंग्य किया था। महायुति में शामिल अजित पवार की एनसीपी से शिवसेना के रिश्ते ठीक नहीं हैं। नासिक और रायगढ़ के पालक मंत्रियों को लेकर दोनों दलों में खींचतान जारी है। ऐसे में हो

सकता है कि शिंदे राज ठाकरे को नया पार्टनर बनाने की सोच रहे हों? बीजेपी छोड़कर नया गठबंधन हालांकि वे बीजेपी को छोड़ कर यह फैसला लेंगे। इसमें संदेह है क्योंकि शिंदे के बाहर जाने पर भी फडणवीस सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जाहिर है कि शिंदे ऐसा करने से बचेंगे। यह अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि राज को साथ लेकर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी समेत एमवीए को करारा धक्का दें, क्योंकि बीएमसी में उद्धव ठाकरे के गुट का ही कब्जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के बाद भी राजनीति जारी है। बीजेपी आज की स्थिति अकेले सरकार बना सकने की स्थिति में खड़ी है। बीजेपी जहां खुद को मजबूत कर रही है तो यहीं कोशिश अजित पवार और एकनाथ शिंदे भी कर रहे हैं। तीनों पार्टियों में विपक्ष के नेताओं का पक्ष प्रवेश इसी का हिस्सा है।

मतदाता सूची में सुधार के लिए महज 89 अपील की गई', चुनाव आयोग ने खारिज किया हेराफेरी का विपक्ष का आरोप

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में हेराफेरी के विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मतदाता सूची में सुधार के लिए महज 89 अपील ही की गई। दरअसल, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मतदाता सूची पर विस्तृत चर्चा की मांग की थी। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र की मतदाता सूची में कथित फर्जीवाड़े और मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबरों के दोहराव का दावा किया था। इससे पहले राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया था कि 2019 से 2024 तक महाराष्ट्र की मतदाता सूची में करीब 30 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस



और आम आदमी पार्टी ने भी मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। अब चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि लगाए गए आरोप तथ्यों से परे हैं। चुनाव आयोग ने दिया जवाब सूत्रों के मुताबिक, 6-7 जनवरी 2025 को प्रकाशित विशेष सारांश संशोधन के दौरान

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 24 के तहत शायद ही कोई पहली या दूसरी अपील की गई हो या मतदाता सूची (धारा 22) या समावेशन (धारा 23) में किसी प्रविष्टि में सुधार किया गया हो। विशेष सारांश संशोधन (एसएसआर) में मतदाता सूची की समीक्षा करना और मतदाता

सूची का मसौदा जारी करना शामिल है। यह अक्सर चुनावों से पहले कराया जाता है। इसका मकसद नए पात्र मतदाताओं को जोड़कर एक न्यायसंगत और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया को बनाए रखना है। इसमें 18 साल के हो चुके लोग या अपना निर्वाचन क्षेत्र बदलने वाले लोग

शामिल हैं। इसमें डुप्लिकेट और मृत मतदाताओं को हटाना भी शामिल है। 'मतदाता सूचियों को निर्विवाद रूप से स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं' सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र में सिर्फ 89 अपील दर्ज की गईं। देश में 13,857,359 बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) थे और मतदाता सूची में बदलाव के लिए केवल 89 अपील की गईं। इसलिए जनवरी 2025 में एसएसआर के पूरा होने के बाद प्रकाशित मतदाता सूचियों को निर्विवाद रूप से स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 'आरोप लगाने वालों ने कानून का पालन करने की भी परवाह नहीं की' चुनाव आयोग के सूत्रों का आगे कहना है कि आरपी अधिनियम 1950 की धारा 24 को 20 सितंबर, 1961 को जोड़ा गया था, जो वर्तमान

मुख्य चुनाव आयुक्त के जन्म से बहुत पहले की बात है। सूत्रों के मुताबिक, अगर कोई कहता है कि जिस मतदाता सूची पर मतदान हुआ है वह सही नहीं है, तो उन्होंने 1961 में सरकार की ओर से प्रस्तावित और 1961 में संसद की ओर से पारित चुनाव कानून का पालन करने की भी परवाह नहीं की है। अगले कुछ महीनों में बिहार और अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए विपक्षी दलों की ओर से इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के आसार हैं। चुनाव आयोग ने पिछले दिनों कई बार कहा है कि ईपीआईसी नंबरों के दोहराव का मतलब डुप्लिकेट या फर्जी मतदाता नहीं है। वह अपने तर्क पर कायम है और अपनी बात को साबित करने के लिए लगातार डेटा जारी कर रहा है।

अमेरिका ने चीन के 125% टैरिफ के जवाब में 245% टैरिफ लगाने का किया एलान

व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक दस्तावेज में कहा गया है कि चीन को अब अमेरिका पर अपनी जवाबी कार्रवाइयों के कारण 245 प्रतिशत तक टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। यह जानकारी तब सामने आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयोजित खनिजों और उससे बने उत्पादों पर अमेरिकी निर्भरता के कारण पैदा हुई जोखिमों की जांच के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप की ओर से जवाबी टैरिफ के एलान के बाद शुरू हुआ टैरिफ वॉर दस्तावेज में ट्रंप के उस दावे का हवाला दिया गया है कि रूविदेशी महत्वपूर्ण खनिजों पर अत्यधिक निर्भरता और उनके खराब उत्पाद अमेरिकी रक्षा क्षमताओं, बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी नवाचार को खतरे में डाल सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि ट्रंप ने सभी देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया है और उन देशों पर पारस्परिक रूप से उच्च टैरिफ लगाए हैं जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा सबसे अधिक है। टैरिफ पर चीन की प्रतिक्रिया के जवाब में अमेरिका ने लिया सख्त फैसला व्हाइट हाउस ने कहा कि 75 से अधिक देश पहले ही नए व्यापार



समझौतों पर चर्चा करने के लिए संपर्क कर चुके हैं। इसे देखते हुए चीन को छोड़कर अन्य देशों पर लगने वाला जवाबी टैरिफ फिलहाल टाल दिया गया है। अमेरिका के अनुसार चीन ने जवाबी कार्रवाई की है इसलिए चीन के उत्पादों पर अमेरिका में आयात पर 245 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया जाएगा। चीन पर सख्ती का अमेरिका ने बताया यह कारण ट्रंप प्रशासन के दस्तावेज में यह भी उल्लेख किया गया है कि चीन ने कुछ महीने पहले अमेरिका को गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी और अन्य प्रमुख उच्च-तकनीकी सामग्रियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिनके सैन्य उपयोग की संभावना थी। इसी सप्ताह चीन छह भारी दुर्लभ रेयर अर्थ मेटल के साथ-साथ रेयर अर्थ चुंबकों के निर्यात को भी निलंबित

कर दिया था। व्हाइट हाउस ने दावा किया कि इस तरह की कार्रवाई दुनिया भर में ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस निर्माताओं, सेमीकंडक्टर कंपनियों और सैन्य ठेकेदारों के लिए महत्वपूर्ण घटकों की आपूर्ति रोकने के लिए की गई। अमेरिका के 245% टैरिफ पर चीन ने दी यह प्रतिक्रिया चीन ने अमेरिका की आरे से लगाए गए 245% टैरिफ पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ट्रंप प्रशासन टैरिफ के आंकड़ों का स्पष्ट बयौरा दे। चीन के आयात पर अमेरिका ने 245 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का एलान किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि अमेरिकी पक्ष को रूविशिष्ट कर दर के आंकड़े के बारे में बताना चाहिए। बुधवार को एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, लिन ने कहा कि चीन ने टैरिफ मुद्दे पर अपनी

स्थिति को बार-बार साफ किया है। उन्होंने कहा कि टैरिफ युद्ध अमेरिका की ओर से शुरू किया गया था और बीजिंग ने अपने वैध अधिकारों और हितों और अंतरराष्ट्रीय निष्पक्षता और न्याय की रक्षा के लिए जवाबी कदम उठाए हैं। ये कदम पूरी तरह से रूचित और कानूनी हैं। उन्होंने कहा कि टैरिफ और व्यापार युद्धों में कोई विजेता नहीं होता है। उन्होंने कहा कि चीन इन युद्धों को लड़ना नहीं चाहता है, लेकिन इनसे डरता भी नहीं है। उन्होंने हाथ मिलाने और बाधाओं को दूर करने के लिए चीन की प्रतिबद्धता व्यक्त की। अमेरिका-चीन के बीच जारी टैरिफ वॉर में अब तक क्या-क्या हुआ? अमेरिका की ओर से 02 अप्रैल 2025 को अपने व्यापारिक साझेदारों पर जवाबी टैरिफ लगाने के एलान के बाद चीन के साथ उसका व्यापार युद्ध एक नए मुकाम पर पहुंच गया। दोनों देश एक-दूसरे पर हर दिन एक नए भारी भरकम टैरिफ का एलान कर रहे हैं। इससे पहले, ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामानों को टैरिफ से छूट दी थी। उस दौरान, चीन ने अमेरिका से सभी इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर जवाबी टैरिफ को पूरी तरह से खत्म करने की अपील की थी।

फ्लैट मालिकों के लिए खुशखबरी, पुराने घर के बदले रिडेवलपमेंट में घर लेंगे तो नहीं देना होगा कोई टैक्स

यदि आपका घर किसी बिल्डर ने रिडेवलपमेंट में लिया है और उसके बदले नया घर दिया है तो इस पर कोई टैक्स की देनदारी नहीं होगी। मुंबई



आयकर अपीलिय न्यायाधिकरण यानी आईटीएटी के पीठ सदस्यों बीआर भास्करन और संदीप गोसाई ने हाल ही में एक फैसले में कहा, मौजूदा आवासीय फ्लैट के बदले में चल रहे पुनर्विकास आवासीय परियोजना में एक नया फ्लैट प्राप्त करना आयकर अधिनियम की धारा 56 के तहत कर योग्य नहीं है। बेंच के अनुसार, यह पुराने फ्लैट के बदले अगर कोई बिल्डर नई बिल्डिंग में फ्लैट देता है तो इसमें किसी तरह का लाभ नहीं होता है। यानी केवल पुराने फ्लैट को नए फ्लैट से बदलने से कोई कर योग्य आय नहीं होती है। अनिल दत्ताराम पितले ने 1997-98 में एक सहकारी समिति में एक फ्लैट खरीदा था। डेवलपर के साथ समझौते के अनुसार, सोसायटी का पुनर्विकास किया गया। पितले को दिसंबर, 2017 में नया फ्लैट आवंटित किया गया था। नए फ्लैट के लिए चुकाए गए स्टांप ड्यूटी मूल्य 25,17,700 रुपये था। पुराने फ्लैट की कीमत 5,43,040 रुपये थी। इस तरह इन दोनों के बीच 19,74,660 रुपये का अंतर था। इस अंतर को आयकर विभाग ने अन्य स्रोतों से आय के रूप में मानकर टैक्स लगा दिया था। इसके खिलाफ पितले ने आईटीएटी में अपील की। आईटीएटी के अनुसार, धारा 56(2)(एक्स) के प्रावधान वर्तमान मामले में लागू नहीं होंगे। इस स्थिति में इन लेनदेन के कारण करदाता पर कोई कर देयता नहीं होगी। कानूनी जानकारों का मानना है कि यह फैसला निश्चित रूप से भविष्य में उन मकान मालिकों के लिए फायदेमंद होगा जो अपने मौजूदा घरों को नए आवासीय प्रोजेक्ट में आलीशान अपार्टमेंट के साथ बदलने पर विचार करेंगे। हालांकि पुराने फ्लैट को खत्म करना और पुराने फ्लैट के बदले नई संपत्ति प्राप्त करना टैक्स के दायरे में नहीं है, लेकिन भविष्य में नई संपत्ति की बिक्री से कैपिटल गेन टैक्स देना होगा।

‘फुले’ की रिलीज पर रोक लगाने से भड़के अनुराग कश्यप, बोले- कोई मुझे समझाओ असली बेवकूफ कौन है?



फिल्म निर्माता और अभिनेता अनुराग कश्यप ने फिल्म ‘फुले’ को लेकर सेंसरशिप मुद्दों पर चिंता जताई है। महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय द्वारा फिल्म को लेकर जताई गई आपत्ति के बाद इसके रिलीज को कथित तौर पर स्थगित कर दिया गया था। अनुराग ने इस बात पर हैरानी जताई की फिल्म रिलीज से पहले ही समुदाय इस तक कैसे पहुंच प्राप्त कर पाया। उन्होंने जातिवाद को लेकर सरकार पर भी सवाल खड़े किए।

अनुराग कश्यप ने क्या कहा? अनुराग कश्यप ने पूरे मामले पर अपनी निराशा जताई। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी साझा की। अनुराग ने लिखा, ‘मेरी जिंदगी का पहला नाटक ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले पर था। भाई अगर जातिवाद नहीं होता इस देश में तो ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले को क्या जरूरत थी लड़ने की। अब एक समुदाय के लोगों को शर्म आ रही है या वो शर्म में मरे जा रहे हैं या फिर एक अलग ही समुदाय भारत में हैं। हम देख नहीं पा रहे हैं, बेवकूफ कौन है कोई तो समझाए?’ सरकार पर भी उठाए सवाल अनुराग का मानना है कि ‘फुले’ उन कई फिल्मों में से एक है, जिन्हें अपने बोलड और बेबाक विषयों के कारण दमन का सामना करना पड़ रहा है। वह ‘पंजाब 95’, ‘तीस’, ‘धड़क 2’ सहित कई फिल्मों का हवाला देते हुए सुझाव देते हैं कि इन फिल्मों को असहज सच्चाई को दर्शाने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। अनुराग ने लिखा, ‘मुझे नहीं पता कि इस जातिवादी, क्षेत्रवादी, नस्लवादी सरकार के एजेंडे को उजागर करने वाली और कितनी फिल्में ब्लॉक की गई हैं। उन्हें अपना चेहरा आईने में देखने में शर्म आती है। उन्हें इतनी शर्म आती है कि वो खुलकर यह भी नहीं बता सकते कि फिल्म में ऐसा क्या है? जो उन्हें परेशान करता है। बकवास।’

कॉमेडी फिल्में करने वाले रितेश विलेन बनकर भी छा गए

गंभीर किरदारों में किया उम्दा अभिनय

रितेश देशमुख ने बॉलीवुड में ज्यादातर कॉमेडी फिल्मों में ही की हैं, इस वजह से उनकी इमेज एक कॉमिक एक्टर की बन चुकी है। रितेश ने पिछले कुछ सालों में ऐसी फिल्मों में भी की हैं, जिनमें वह विलेन का किरदार निभाते भी नजर आए, साथ ही कुछ फिल्मों, सीरीज में गंभीर किरदारों में दिखे। जानिए, कौन सी हैं, वो फिल्मों और सीरीज।

रेड 2

जल्द ही अजय देवगन की फिल्म ‘रेड 2’ रिलीज होगी। इस फिल्म में अजय देवगन ने एक इनकम टैक्स ऑफिसर का रोल किया है। फिल्म में वह एक राजनेता के घर पर छापा मारते हैं, इस नेता का किरदार रितेश देशमुख निभा रहे हैं। फिल्म का विलेन रितेश का किरदार ही है। अब तक फिल्म ‘रेड 2’ की जो झलक मिली है, उसमें विलेन के तौर पर रितेश काफी प्रभावित करते दिख रहे



हैं। रितेश का लुक, डायलॉग काफी दमदार लग रहे हैं। इस फिल्म को राजकुमार गुप्ता ने निर्देशित किया है। **एक विलेन** फिल्म ‘एक विलेन (2014)’ में लीड रोल सिद्धार्थ मल्होत्रा और श्रद्धा कपूर ने किया था। फिल्म में रितेश ने एक साइको किलर का रोल किया। इस फिल्म में विलेन के तौर पर रितेश को देखकर दर्शक हैरान हो गए। फिल्म के निर्देशक मोहित सूरी हैं।

मरजावां

‘एक विलेन’ फिल्म करने के बाद रितेश देशमुख फिल्म ‘मरजावां (2019)’ में भी विलेन बने। इस फिल्म में उनका विलेन का किरदार जरा हटकर रहा। फिल्म में उन्होंने एक बौने का रोल किया, जो की माफिया से जुड़ा है। फिल्म में रितेश के किरदार के कारण हीरोइन (तारा सुतारिया) की मौत हो जाती है। ऐसे में फिल्म का हीरो (सिद्धार्थ मल्होत्रा) रितेश के किरदार से बदला लेता है। इस फिल्म के

निर्देशक मिलाप मिलन जवेरी थे।

लय भारी

साल 2014 में रितेश देशमुख ने एक मराठी फिल्म ‘लय भारी’ की थी। इस फिल्म में रितेश ने डबल रोल किया। एक रोल सीधे-सादे शख्स का था, तो दूसरा किरदार एक गुंडे का रहा। दोनों ही किरदारों में रितेश गंभीर नजर आए। इस फिल्म में रितेश की पत्नी और एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा ने कैमियो किया था। साथ ही सलमान खान भी कैमियो रोल में ‘लय भारी’ में नजर आए। इस फिल्म को निशिकांत कामत ने निर्देशित किया था। पिल सीरीज में निभाया सीरियस रोल रितेश देशमुख ने एक सीरीज ‘पिल’ भी की। यह एक मेडिकल थ्रिलर सीरीज थी। इसमें रितेश ने एक सरकारी ऑफिसर का रोल निभाया था, जो मेडिकल, दवा माफिया के खिलाफ जंग लड़ता है।

2022 के बाद पहली बार आईपीएल में सुपर ओवर से निकला नतीजा, राजस्थान को हराकर शीर्ष पर पहुंची दिल्ली

दिल्ली कैपिटल्स ने बुधवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2025 के मैच में सुपर ओवर में राजस्थान रॉयल्स को हराया। राजस्थान ने सुपर ओवर में 11 रन बनाए थे, लेकिन दिल्ली ने चार गेंदों पर ही मुकाबला अपने नाम कर लिया। सुपर ओवर में दिल्ली के लिए केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स आए थे और स्टब्स ने छक्का लगाकर दिल्ली को जीत दिलाई। 2022 के बाद यह पहली बार है जब आईपीएल में किसी मैच का नतीजा सुपर ओवर के जरिये निकला है। इस जीत के साथ ही दिल्ली की टीम अंक तालिका में शीर्ष पर आ गई। उसके छह मैचों में पांच जीत और एक हार के साथ 10 अंक हो गए हैं। सुपर ओवर में बेहतर है दिल्ली का रिकॉर्ड

आईपीएल में अब तक 15 मैच टाई रहे हैं। सुपर ओवर में दिल्ली का रिकॉर्ड अच्छा रहा है और उसने पांच में चार मुकाबले जीते हैं। दिल्ली ने सुपर ओवर में राजस्थान को हराने से पहले 2021 में सनराइजर्स हैदराबाद, 2020 में पंजाब किंग्स,

2019 में कोलकाता नाइट राइडर्स और 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को हराया था। हालांकि, 2013 में उसे सुपर ओवर में आरसीबी के हाथों हार मिली थी। दिल्ली की टीम आईपीएल में सबसे ज्यादा सुपर ओवर मैच जीतने वाली टीम बन गई है। उसने इस मामले में पंजाब किंग्स को पीछे छोड़ा जिसने चार मैचों में तीन बार सफलता हासिल की है।

निर्धारित ओवर के बाद बराबरी पर छूटा मुकाबला

दिल्ली और राजस्थान के बीच 20 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बराबरी पर छूटा जिसके बाद मैच का फैसला सुपर ओवर से कराने का फैसला हुआ। दिल्ली ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 188 रन बनाए थे। राजस्थान की टीम यशस्वी जायसवाल और नीतीश राणा के अर्धशतकों के अच्छी स्थिति में दिख रही थी, लेकिन टीम निर्धारित ओवर में चार विकेट पर 188 रन ही बना सकी। इस तरह मुकाबला बराबरी पर छूटा। सुपर ओवर में हालांकि, राजस्थान की टीम पूरे छह गेंद भी



नहीं खेल सकी और उसने पांच गेंदों पर दो विकेट गंवा दिए। इस तरह दिल्ली को सुपर ओवर में लक्ष्य हासिल करने में कोई परेशानी नहीं हुई।

सुपर ओवर का रोमांच

सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए सबसे पहले राजस्थान की टीम उतरी। राजस्थान की ओर से शिमरॉन हेटमायर और रियान पराग बल्लेबाजी के लिए आए, जबकि दिल्ली ने तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को गेंद थमाई। पहली गेंद पर कोई रन नहीं आया और दूसरी गेंद पर हेटमायर ने चौका लगाया। तीसरी गेंद पर हेटमायर ने एक रन लिया और स्ट्राइक पर पराग आए। चौथी गेंद पर पराग ने चौका लगाया,

लेकिन यह नो बॉल करार दी गई। स्टार्क ने फ्री हिट पर वाइड गेंद फेंकी, लेकिन पराग दौड़ पड़े और रन आउट हो गए। पराग चार रन बनाकर आउट हुए और क्रीज पर यशस्वी जायसवाल उतरे। अगली गेंद पर हेटमायर ने शॉट लगाया और दो रन के लिए भागे। हालांकि, एक ही रन पूरा हुआ और टीम सुपर ओवर पूरा नहीं खेल सकी। राजस्थान ने पांच गेंदों पर 11 रन बनाए। सुपर ओवर में लक्ष्य का बचाव करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की ओर से केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स आए। राजस्थान ने गेंद संदीप शर्मा को थमाई। पहली गेंद पर केएल राहुल ने दो रन निकाले। राहुल ने अगली गेंद पर चौका लगाया। तीसरी गेंद पर एक

रन आया और स्टब्स स्ट्राइक पर आए। चौथी गेंद पर स्टब्स ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। इससे पहले, लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान ने अच्छी शुरुआत की थी और पावरप्ले तक कोई विकेट नहीं गंवाया था। कप्तान संजू सैमसन हालांकि 19 गेंदों पर 31 रन बनाकर रिटायर हट हो गए और मैदान पर दोबारा वापस नहीं आए। रियान पराग आठ रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद यशस्वी ने नीतीश राणा के साथ मिलकर 50+ रनों की साझेदारी की। यशस्वी ने इस सीजन का अपना दूसरा अर्धशतक जड़ा, लेकिन वह 37 गेंदों पर तीन चौकों और चार छक्कों की मदद से 51 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद नीतीश राणा ने मोर्चा संभाला और 26 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। नीतीश भी फिर ज्यादा देर नहीं टिक सके और 28 गेंदों पर छह चौकों और दो छक्कों की मदद से 51 रन बनाकर आउट हुए। राजस्थान के लिए ध्रुव जुरेल और शिमरॉन हेटमायर क्रीज पर थे और सेट हो चुके थे। राजस्थान को आखिरी

ओवर में जीत के लिए नौ रन बनाने थे, लेकिन मिचेल स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ आठ रन दिए। अंतिम गेंद पर दो रन चाहिए थे। जुरेल ने शॉट मारा और दो रन के लिए भागे, लेकिन दूसरा रन पूरा नहीं कर सके। जुरेल 17 गेंदों पर दो छक्के की मदद से 24 रन बनाकर आउट हुए, जबकि हेटमायर 15 रन बनाकर नाबाद लौटे। राजस्थान की ओर से मिचेल स्टार्क, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने एक-एक विकेट लिए। राजस्थान ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। दिल्ली के लिए कोई बल्लेबाज बड़ी पारी तो नहीं खेल सका, लेकिन उन्होंने टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया जिससे टीम चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने में सफल रही। दिल्ली के लिए अभिषेक पोरेल ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए, जबकि केएल राहुल ने 38 रनों का योगदान दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जैक फ्रेजर मैकगर्क और पोरेल ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने मैकगर्क को नौ रन पर आउट किया।

प्रोटीन से भरपूर मांसाहार या फाइबरयुक्त शाकाहार, वेज और नॉनवेज में ज्यादा फायदेमंद क्या है

व्यक्ति का खान-पान न सिर्फ उसके शरीर को पोषण देता है, बल्कि स्वास्थ्य, ऊर्जा स्तर और जीवनशैली पर सीधा असर डालता है। आहार की बात करें तो दुनिया में खाने की कई वैरायटी हैं। कुछ लोग शाकाहारी होते हैं तो कुछ मांसाहारी। कई लोगों को लगता है कि शरीर की ताकत बढ़ाने, प्रोटीन की पूर्ति के लिए आहार में नॉनवेज फूड खाना चाहिए। वहीं अक्सर सुना होगा कि कई सेलेब्स ने नॉनवेज खाना छोड़कर पूरी तरह से शाकाहार को अपना लिया। अब सवाल है कि जब मांसाहार फायदेमंद है तो उसे छोड़ कुछ लोग शाकाहार क्यों अपनाते हैं। जब बात आती है शाकाहारी और मांसाहारी भोजन की, तो अक्सर यह सवाल उठता है, कौन सा ज्यादा बेहतर और फायदेमंद है? चलिए जानते हैं वेज और नॉनवेज भोजन के फायदे, नुकसान और यह भी कि आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर हो सकता है।

शाकाहारी भोजन के फायदे शाकाहारी भोजन के सेवन से कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। वेज फूड हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ ही वजन को नियंत्रित रखने में मददगार है। शाकाहारी भोजन का सेवन पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के साथ ही कैंसर और डायबिटीज के खतरे को भी कम कर सकता है। हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा शाकाहारी भोजन में फाइबर,



एंटीऑक्सीडेंट और कम सैचुरेटेड फैट होता है, जिससे हृदय रोगों का खतरा कम होता है।

वजन नियंत्रण में मददगार हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज से भरपूर वेज डाइट वजन कम करने या नियंत्रित रखने में मदद करती है।

पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद फाइबर युक्त आहार पाचन को बेहतर बनाता है और कब्ज जैसी समस्याएं नहीं होतीं।

कैंसर और डायबिटीज का खतरा कम शोध बताते हैं कि शाकाहारी लोग टाइप 2 डायबिटीज और कुछ प्रकार के कैंसर से प्रभावित होते हैं। मांसाहारी भोजन के फायदे

शाकाहारी खाने के विभिन्न लाभ हैं तो मांसाहार भी शरीर को कई स्वास्थ्य फायदे दे सकता है। नॉनवेज खाने से प्रोटीन की पूर्ति होती है, विटामिन और मिनिरल्स की कमी को दूर करते हैं और मांसपेशियों के तेजी से विकास में सहायक है। आइए जानते हैं नॉनवेज के फायदे,

प्रचुर मात्रा में प्रोटीन अंडा, चिकन, मछली, मीट जैसे स्रोतों से शरीर को उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन मिलता है जो मांसपेशियों के लिए जरूरी होता है।

विटामिन और मिनिरल्स की पूर्ति मांस, अंडे और मछली में विटामिन B12, आयरन, जिंक जैसे जरूरी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं।

मांसपेशियों का तेजी से विकास फिटनेस और बॉडीबिल्डिंग करने वालों के लिए मांसाहारी डाइट फायदेमंद होती है।

वेज और नॉनवेज भोजन के संभावित नुकसान - फोटो : adobe वेज और नॉनवेज भोजन के संभावित नुकसान

अगर डाइट में दालें, सोया, पनीर जैसे प्रोटीन स्रोत न हों तो शरीर में कमजोरी या मांसपेशियों की कमी हो सकती है। इसके अलावा विटामिन बी 12 और आयरन जैसे पोषक तत्व मुख्य रूप से मांसाहारी चीजों में पाए जाते हैं जिनकी पूर्ति शाकाहार में थोड़ी कठिन हो सकती है।

मांसाहारी भोजन के संभावित

नुकसान

रेड मीट और फैटी मांस के अधिक सेवन से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और दिल की बीमारियों का खतरा हो सकता है। साथ ही अधिक मांस खाने से कब्ज और एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। ये पाचन तंत्र के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर मांसाहारी भोजन का सेवन संतुलित नहीं हो तो यह मोटापा बढ़ा सकता है।

शाकाहार और मांसाहार में से ज्यादा फायदेमंद क्या - फोटो : Adobe वेज और नॉनवेज में ज्यादा बेहतर क्या है ?

शाकाहारी भोजन लंबी उम्र, बेहतर दिल की सेहत और हल्के शरीर के लिए जाना जाता है। वहीं मांसाहारी भोजन प्रोटीन और कुछ जरूरी पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है। किसी भी डाइट का सही या गलत होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कितनी संतुलित और पोषणयुक्त बनाते हैं। यदि आप फिटनेस, मांसपेशियों की ग्रोथ या ऊर्जा के लिए डाइट प्लान कर रहे हैं तो संयमित रूप से मांसाहार फायदेमंद हो सकता है और अगर आप स्वस्थ हृदय, बेहतर पाचन और लंबी उम्र चाहते हैं, तो संतुलित शाकाहारी आहार बेहतर विकल्प है। दोनों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं लेकिन कुछ अध्ययनों में शाकाहारी आहार को नॉनवेज की तुलना में स्वास्थ्य के लिए बेहतर बताया गया है।

तेज धूप और बढ़ता तापमान आंखों के लिए भी ठीक नहीं



देशभर में बढ़ती गर्मी के साथ कई प्रकार की बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। जैसे-जैसे पारा बढ़ता जा रहा है, ये स्थिति स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को भी बढ़ाती जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, लगातार धूप-गर्मी के संपर्क में रहने वाले, हीटस्ट्रोक के शिकार लोगों में लिवर-किडनी, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ने का जोखिम हो सकता है। इसके अलावा गर्मी का ये मौसम आपकी आंखों के लिए भी समस्याएं बढ़ाने वाला हो सकता है। धूप और गर्मी का आपकी आंखों पर कई तरह से असर हो सकता है, मुख्य रूप से सूरज की रोशनी के संपर्क, उच्च तापमान के कारण एलर्जी, ड्राई आईज, फोटोकेराटाइटिस, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस और आंखों में थकान की समस्या हो सकती है। इस तरह के जोखिमों से बचे रहने के लिए सभी लोगों को आंखों की विशेष देखभाल करते रहना चाहिए। आजकल स्क्रीन ज्यादा देखने से लोगों को कम उम्र में ही आंखों की समस्याएं होने लगी हैं। मोबाइल, लैपटॉप के अधिक इस्तेमाल से देखने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है साथ ही आंखें कमजोर भी होने लगती हैं। इसके अलावा कुछ लोग आंखों को गलत तरीके से धोते हैं, जिससे आंखों से जुड़ी अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। गर्मी के दिनों में आंखें धोने से जलन और सूजन में काफी आराम मिलता है। हालांकि अगर आप गर्मी में ठंडे पानी से आंखें धो रहे हैं तो इसके लिए पहले सही तरीका जान लेना अच्छा होता है। आंखों को सही तरीके से धोना जरूरी गलत तरीके से आंखों को धोना कई बार नुकसानदायक भी हो सकता है। अगर आप आंखों को धो रहे हैं तो इसके लिए आंखों को बंद करके उसके ऊपर से ठंडे पानी के छींटे मारने चाहिए। इससे आंखों पर चोट नहीं लगती है।

इसके लिए सिर को सिंक या पीछे की ओर न करते हुए थोड़ा सा झुककर आंखों को धोना चाहिए। इसके बाद आंखों को धीरे-धीरे करके खोलें और किसी साफ कपड़े से पोछें। कई बार ठंडे पानी के छींटे आंखों में जाने से आंखों में मौजूद टिशू प्रभावित हो सकते हैं। इसके साथ ही आंखों को धोने से पहले आपको हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए।

बिना नोटिस आव्रजन दर्जा खत्म हुआ तो अमेरिकी कोर्ट पहुंचा भारतीय छात्र; जानिए चिन्मय देवरे के बारे में

अमेरिका से अप्रवासियों के निर्वासन का सिलसिला लगातार जारी है। मगर अब बीजा लेकर रह रहे लोगों को भी निर्वासित करने के लिए उनका आव्रजन दर्जा खत्म किया जा रहा है। ऐसे ही एक मामले में अब अमेरिकी गृह विभाग और आव्रजन अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस बार मुकदमा चार छात्रों ने दर्ज कराया है। इसमें एक भारतीय छात्र चिन्मय देवरे भी शामिल है। छात्र का कहना है कि उसके आव्रजन दर्जे को बिना नोटिस और सूचना दिए समाप्त कर दिया गया। जबकि उनके खिलाफ न तो कोई मुकदमा है और न ही वे किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल रहे हैं। आव्रजन अधिकारियों की कार्यवाही

से भारतीय छात्र चिन्मय देवरे समेत तीन अन्य छात्रों का करियर खतरे में पड़ गया है। आइए जानते हैं चिन्मय देवरे कौन हैं और मामला क्या है? चिन्मय देवरे कौन हैं.. मिशिगन के अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (ACLU) ने छात्रों की ओर से दायर मुकदमे में कहा कि चिन्मय देवरे वेन स्टेट यूनिवर्सिटी से स्नातक कर रहे हैं। वे 2004 में एच 4 आश्रित बीजा लेकर अपने परिवार के साथ अमेरिका आए। उन्होंने और उनके परिवार ने 2008 में अमेरिका छोड़ दिया। मगर 2014 में उनका परिवार वापस आ गया। मिशिगन में हाईस्कूल पूरा करने के बाद चिन्मय ने एच-4 स्थिति के तहत वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। जहां से वह



2021 से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक कर रहे हैं। चिन्मय ने मई 2022 में आवेदन किया और उन्हें एच-4 स्टेटस की उम्र खत्म होने पर एफ-1 छात्र का दर्जा पाने की अनुमति दे दी गई। मई 2025 में वे अपना कोर्स पूरा करके स्नातक हो जाएंगे। चिन्मय ने स्नातक करने के बाद F-1 दर्जे के अनुसार वैध

रोजगार प्राप्त करने की योजना बनाई थी। चिन्मय कैटन में अपने परिवार के साथ रहते हैं। मुकदमे के अनुसार, देवरे पर कभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है या उसे दोषी नहीं ठहराया गया है। वह किसी भी राजनीतिक मुद्दे को लेकर कैप्स में विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय

नहीं रहा है। अब जानिए मामला क्या है चार अप्रैल को वेन स्टेट यूनिवर्सिटी से छात्र देवरे को ईमेल मिला। इसमें कहा गया कि छात्र और विनिमय आगंतुक सूचना प्रणाली (एसईवीआईएस) में उनका एफ-1 छात्र का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। समाप्ति का कारण था कि अन्यथा स्थिति बनाए रखने में विफल होना, आपराधिक रिकॉर्ड जांच में पहचाने गए व्यक्ति बताकर उनका बीजा रद्द कर दिया गया है। जबकि कोई और विवरण या आरोप नहीं दिए गए। उनका आपराधिक, सिविल और आव्रजन रिकॉर्ड लगभग साफ होने के अलावा उन्हें विदेश विभाग से कोई नोटिस भी नहीं मिला कि उनका कोई एफ-1 बीजा रद्द कर दिया गया

है। मुकदमे में कहा गया है कि इन बर्खास्तगी ने वादी की शिक्षा, शोध और करियर को खतरे में डाल दिया है। अब वे रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते। साथ ही मास्टर डिग्री के लिए दूसरे स्कूल में जा सकते हैं। यदि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से निकाल दिया जाता है, तो उसे उसके माता-पिता और बहन से भी अलग कर दिया जाएगा। मुकदमे में अदालत से इन छात्रों की स्थिति बहाल करने की मांग की गई है ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और हिरासत और निर्वासन के जोखिम से बच सकें। तीन अन्य छात्रों का आव्रजन दर्जा भी रद्द चिन्मय देवरे के अलावा तीन अन्य छात्रों का आव्रजन दर्जा रद्द किया गया है।

मुंबई में डिनर डिप्लोमेसी, पुणे में 'खेला', एकनाथ शिंदे ने यूबीटी के बाद मनसे में लगाई सेंध, पवार के लिए बने चुनौती

मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति से नीतिमत्ता अब पूरी तरह से समाप्त हो गई है। ऐसी चर्चा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे के बीच मंगलवार की रात डिनर डिप्लोमेसी के बाद चल रही है। चर्चा की वजह यह है कि मंगलवार की रात राज ठाकरे के घर दावत पर पहुंचने से पहले शिंदे ने राज ठाकरे के लिए पुणे में खेला करके आए थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शहर उपाध्यक्ष संदीप मोहिते पाटिल को

'फोड़' कर अपनी पार्टी शिवसेना में शामिल करने के बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, राज ठाकरे के घर दावत खाने पहुंचे थे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को राज ठाकरे को बड़ा झटका दिया था। राज की पार्टी मनसे के पुणे शहर के उपाध्यक्ष, युवा उद्यमी एवं जाने-माने फिल्म निर्माता संदीप मोहिते पाटिल ने मंगलवार को राज का इंजन छोड़कर अपने सहयोगियों के शिंदे की शिवसेना का धनुष बाण अपने हाथ में थाम लिया था। अजित पवार के लिए चुनौती बने



शिंदे डिप्टी सीएम शिंदे की मौजूदगी में आयोजित समारोह के दौरान संदीप मोहिते पाटिल और उनके समर्थकों का पक्ष प्रवेश कार्यक्रम



संपन्न हुआ। निकट भविष्य में होने वाले पुणे नगर मनपा के चुनावों की पृष्ठभूमि में यह राज की मनसे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो

वहीं पूर्व कांग्रेसी विधायक रवींद्र धांगेकर के बाद संदीप मोहिते पाटिल के शिंदे की शिवसेना में शामिल होने से उप मुख्यमंत्री अजित पवार की राकां के लिए चुनौती बढ़ गई है। अमित की राह में अड़ंगा बने थे शिंदे इससे पहले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में माहिम विधानसभा सीट से मनसे के उम्मीदवार रहे अमित ठाकरे के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार कर राज ठाकरे को बड़ा झटका दिया था। हालांकि, शिंदे की

शिवसेना के उम्मीदवार रहे सदा सरवणकर माहिम विधानसभा क्षेत्र से ही पहले विधायक चुने जाते रहे हैं लेकिन राज पुत्र अमित को विधानसभा में भेजने के लिए बीजेपी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार ने बीजेपी महायुक्ति के घटक दलों से अमित को समर्थन देने की अपील की थी। लेकिन, सरवणकर और शिंदे नहीं माने नतीजतन त्रिकोणीय मुकाबले में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) के उम्मीदवार महेश बलिराम सावंत चुनाव जीतने में सफल हुए थे।

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती एयरपोर्ट का किया उद्घाटन

अमरावती: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को बहुप्रतीक्षित अमरावती एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए इसे जिले के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए पहले विमान से वे स्वयं अमरावती पहुंचे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अमरावती में दक्षिण-पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण स्कूल शुरू किया जा रहा है, जिससे अमरावती जल्द ही विश्व मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। अब हर साल अमरावती से 180 पायलटों को प्रशिक्षित किया जाएगा और लगभग 34 विमान खड़े किए जाएंगे। ये विमान प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। पायलट प्रशिक्षण स्कूल के आगमन से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। नौकरियां बढ़ेंगी। मोदी सरकार के कार्यकाल में मिली यह एक बड़ी सौगात है। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोले, मंत्री



चंद्रशेखर बावनकुले, गिरीश महाजन एवं पूर्व सांसद व भाजपा नेता नवनीत राणा उपस्थित थे। 2 घंटे में अमरावती से मुंबई लंबे इंतजार के बाद अमरावती हवाई अड्डा अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है। बुधवार को अलायंस एयरलाइंस की पहली 72 सीटर फ्लाइट अमरावती एयरपोर्ट पर उतरी। इस ऐतिहासिक

उड़ान में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार समेत राज्य कैबिनेट के कई सदस्य मौजूद थे। हालांकि, यह पहली उड़ान विशेष रूप से वीआईपी यात्रियों के लिए थी, लेकिन अब यह सेवा सामान्य नागरिकों के लिए भी उपलब्ध हो गई है। इससे अमरावती के लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। जहां पहले अमरावती से मुंबई तक ट्रेन से लगभग 12 घंटे का समय लगता था, वहीं अब विमान सेवा से यह दूरी केवल 2 घंटे में तय की जा सकेगी। इससे यात्रियों को 10 घंटे की सीधी बचत होगी। हवाई सेवा के शुरू होने से अमरावती क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने गृहनगर से जुड़े भावनात्मक रिश्ते को साझा किया। उन्होंने कहा कि अमरावती का मुझ पर कर्ज है। अगर अमरावती में कुछ अच्छा होता है, तो मेरी मां सबसे ज्यादा खुश होती है।

खत्म हुई लाडकी बहिन योजना! ये क्या कह गए आदित्य ठाकरे, बोले- अब इन महिलाओं पर घोटाले का आरोप

नासिक: नासिक में आज 16 अप्रैल को शिवसेना यूबीटी का शिविर आयोजित किया गया है। इस शिविर में शिवसेना यूबीटी के बड़े नेता उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत आदि नेता भी शामिल हैं। इस शिविर में शिवसैनिकों की भीड़ के बीच आदित्य ठाकरे ने लाडकी बहिन योजना पर टिप्पणी की। शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने बुधवार को दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख लाडकी बहिन योजना "लगभग खत्म हो गई है" और सत्तारूढ़ सरकार लाखों महिलाओं को लाभार्थी सूची से हटाने की योजना बना रही है।



आदित्य ठाकरे ने यहां पार्टी के एक कार्यक्रम में दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार केवल निर्वाचन आयोग के "आशीर्वाद" के कारण सत्ता में है। उन्होंने सत्तारूढ़ महायुक्ति गठबंधन को "राक्षसी" करार दिया। शिवसेना (यूबीटी) नेता ठाकरे ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बयान के एक दिन बाद यह प्रतिक्रिया दी, जिन्होंने कहा था कि लाडकी बहिन योजना के लिए बजटीय आवंटन किया गया है और इसे खत्म करने का कोई सवाल ही नहीं है।

मुंह से छीन लिया निवाला...डूब जाएगा महाराष्ट्र! महायुक्ति की चाल पर भड़के अबू आजमी, बोले- मतलब निकल गया

मुंबई: महाराष्ट्र में माझी लाडकी बहिन योजना को लेकर घमासान शुरू हो गया है। सरकार ने लाडकी बहिन योजना के तहत महिलाओं को प्रदान की जाने वाली राशि घटा दी है। इस मामले में विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। विपक्ष ने दावा कर दिया है कि इस योजना का बंद होना लगभग तय है। इस मामले में अब महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अबू आजमी भी कूद पड़े हैं। अबू आजमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में अबू

आजमी ने सरकार की जमकर आलोचना की है। अबू आजमी ने शेयर किया पोस्ट अबू आजमी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मतलब निकल गया तो जानते नहीं, ऐसे जा रहे हैं जैसे पहचानते नहीं !! लाडकी बहिन योजना के लिए पात्रता की जांच पहले क्यों नहीं की गई? यह जग जाहिर है की 'लाडकी बहिन योजना' महायुक्ति सरकार की चुनावी चाल थी। सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया, यहां तक की मासूम बच्चों के मुंह से निवाला भी छीन लिया गया।" अबू आजमी ने आगे



अपनी पोस्ट में धोखाधड़ी की आरोप लगाते हुए लिखा, "जनता के साथ ऐसी

खुली धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। इसी तरह अगर सरकारें बनने लगे तो राज्य कर्ज में डूब जाएगा और सरकारी खजाना कंगाल हो जाएगा। जिस सरकार की बुनियाद ही झूट पर हो वो महाराष्ट्र की जनता का भला कैसे कर सकती है?" आपको बता दें कि इससे पहले शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस भी सरकार की इस योजना की जमकर आलोचना कर चुकी है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 'लाडकी बहिन' योजना के

तहत राशि घटाए जाने के दावे वाली खबर को लेकर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यही भाजपा का 'जुमला मॉडल' है। राशि 1500 रुपये प्रतिमाह से घटाकर किया 500 पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने जिस खबर का हवाला देकर भाजपा पर निशाना साधा, उसमें कहा गया है कि इस योजना के तहत आठ लाख महिलाओं की सहायता राशि 1500 रुपये से घटाकर सिर्फ 500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।